# चीनी मिलों को दूसरा राहत पैकेज जल्द देने की तैयारी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी दूर करने के मद्देनजर केंद्र सरकार गन्ना किसानों को सहूलियत देने के लिए चीनी मिलों को एथेनॉल पर दूसरा राहत पैकेज देने की तैयारी में है।

सरकार उन्हें एथेनॉल की क्षमता बढ़ाने को पांच साल के लिए कम ब्याज (6 फीसदी) पर 10 से 12 हजार करोड़ रुपये तक की ऋण मुहैया कराई जा सकती है। सरकार बजट से पहले इसकी घोषणा कर सकती है। इससे पहले सितंबर, 2018 में चीनी मिलों को राहत दी गई थी। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गन्ने की रोपाई से एथेनॉल बनाने को मिल लगाने के लिए भी पैकेज दिया जा सकता है। मंत्रालय की ओर से विभिन्न स्तरों पर गन्ना किसानों को राहत देने के लिए पेशकश की गई है। अब कैबिनेट को निर्णय लेना है कि किन मामलों में चीनी मिलों को कम ब्याज पर ऋण देना है। उन्होंने बताया कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि भुगतान के बावजूद किसानों का बकाया बढ़कर 11,000 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। सरकार चाहती है कि यह बकाया आने वाले चुनावों के दौरान मुद्दा नहीं बने। ब्यूरो

**11,000 करोड़ रुपया अब भी बकाया है किसानों का**

## नाकाफी रहे सरकारी प्रयास

सरकार की ओर से पिछले साल एफआरपी बढ़ाने के अलावा चीनी मिलों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए गए थे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी देशों में संभावनाएं तलाशी गई थीं। हालांकि, सरकार के ये कदम पूरा बकाया चुकाने के मद्देनजर नाकाफी साबित हुए। यूपी सरकार ने भी एक दिन पहले कम ब्याज पर ऋण देने की पेशकश की है।

Amar Ujala

9/1/2019